

[2024] 8 एस. सी. आर 633:2024 आई. एन. एस. सी. 604

जलालुद्दीन खान

बनाम

भारत संघ

(2024 की आपराधिक अपील संख्या 3173)

13 अगस्त 2024

[अभय एस. ओका* और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत आने वाले अपराधों के लिए जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) के तहत ध्यान में रखे जाने वाले कारक।

हेडनोट्स†

जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है-सिद्धांत-सख्त शर्त के साथ कानून-इसकी प्रयोज्यता:

अभिनिर्धारित किया: धारा 43डी (5) के प्रावधानों के तहत आने वाले जमानत के आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत को लघु-सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है-केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना है-अदालत को यह तय करने के लिए आरोप पत्र का एक हिस्सा बनने वाली सामग्री की जांच करनी है कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं-ऐसा करते समय, अदालत को आरोप पत्र को वैसे ही लेना चाहिए जैसे कि-जब जमानत देने के लिए कोई मामला बनाया जाता है, तो अदालतों को जमानत देने में कोई

संकोच नहीं होना चाहिए-अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं-लेकिन न्यायालयों का कर्तव्य है कानून के अनुसार जमानत देने के लिए मामले पर विचार करना -

“जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है "एक स्थापित कानून है-यहां तक कि कानूनों के मामलों में भी जहां जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें हैं, वही नियम केवल एक संशोधन के साथ अच्छा मानता है कि जमानत दी जा सकती है यदि कानून में शर्तें पूरी हो जाती हैं- नियम का यह भी अर्थ है कि एक बार जमानत देने के लिए मामला बनाया जाता है, तो अदालत जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती-यदि अदालतें योग्य मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा। [पैरा 15,21]

केस लॉ उद्धृत किया गया

शोमा कांति सेन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य [2024] 4 एससीआर 270: (2024) 6 एससीसी 591:2024 आई. एन. एस. सी. 269; गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और दूसरा [2024] 2 एस. सी. आर. 134: (2024) 5 एससीसी 403:2024 आई. एन. एस. सी. 92; राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली [2019] 5 एससीआर 1060: (2019) 5 एससीसी 1:2019 आई. एन. एस. सी. 456-संदर्भित।

थवाहा फसल बनाम भारत संघ [2021] 8 एससीआर 797: (2022) 14 एससीसी 766:2021 आई. एन. एस. सी. 688-निर्भर।

अधिनियमों की सूची

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967।

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत नियम है और जेल अपवाद है; प्रथम दृष्टया; मिनी-ट्रायल।

मामले से उद्गत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की अपराधिक अपील सं. 1672-1675 में 2024 की आपराधिक अपील संख्या 3173

2023 के सी.आर.ए.डी.बी. संख्या 514 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 28.11.2023 से

दलों के लिए उपस्थिति

सुश्री मुक्ता गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, शेख सैपन दस्तगीर, रिज़वान अहमद, सुश्री नित्या गुप्ता, पारस नाथ सिंह, हिमांशु गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., मृगांक पाठक, रजत नायर, सुश्री शगुन ठाकुर, सुश्री चित्रांगदा रस्तवारा, सुश्री नीलाक्षी भदौरिया, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति

वास्तविक पहलू

1. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121ए और 122 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) और गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, 1967 (संक्षेप में यू. ए. पी. ए.) की धारा 13, 18, 18ए और 20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। 7 जनवरी 2023 को एक आरोप पत्र दायर किया गया था। उसे आरोप पत्र में आरोपी सं. 2 के रूप में दिखाया गया है। अपीलार्थी ने यू. ए. पी. ए. के तहत विशेष अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, अपीलार्थी और कुछ सह-अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया। विवादित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी द्वारा की गई जमानत की

प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि सह-अभियुक्त को जमानत दी गई थी।

प्रस्तुतियाँ

2. वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मुक्ता गुप्ता का कहना है कि अपीलार्थी को यू. ए. पी. ए. के तहत अपराधों से जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने बताया कि, सबसे अधिक, आरोप यह है कि अपीलार्थी की पत्नी अहमद पैलेस के नाम से जानी जाने वाली एक इमारत की मालिक थी और अपीलार्थी ने गुप्त रूप से दिखाया था कि उक्त इमारत की पहली मंजिल पर परिसर एक अतहर परवेज को किराए पर दिया गया था- आरोपी सं. 1 आरोप है कि पहली मंजिल के परिसर का उपयोग पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी. एफ. आई.) नामक संगठन की आपत्तिजनक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र को वैसे ही लेते हुए, पी. एफ. आई. और अपीलार्थी की गतिविधियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है। यहां तक कि अपीलार्थी को पी. एफ. आई. से जोड़ने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। उसने प्रस्तुत किया कि विभिन्न लोग इमारत में अन्य परिसरों में रहते हैं। इस इमारत में एक पैथोलॉजी प्रयोगशाला, एक क्लिनिक और दुकानें हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए, संपत्ति पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उसने प्रस्तुत किया कि यदि पी. एफ. आई. की गतिविधियाँ वास्तव में अपीलार्थी की मिलीभगत से इमारत में की जा रही थीं, तो वह संपत्ति के अंदर सी. सी. टी. वी. कैमरे नहीं लगाएगा। वह प्रस्तुत करेगी कि अपीलार्थी का मामला यू. ए. पी. ए. की धारा 43डी (5) द्वारा निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट करता है, क्योंकि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने **शोमा कांति सेन बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा** मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

3. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, भारत की विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने संरक्षित गवाहों वी, वाई और जेड के बयानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने बताया कि इमारत अहमद पैलेस की जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि 6 और 7 जुलाई 2022 को, अपीलार्थी और आरोपी सं. 1 को इमारत की पहली मंजिल से कुछ वस्तुओं को स्थानांतरित करते देखा गया। जब पुलिस ने 11 जुलाई 2022 को छापा मारा, तो वे वस्तुएँ नहीं मिलीं, और इसलिए, अपीलार्थी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.16 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि संरक्षित गवाह जेड ने खुलासा किया कि 29 मई 2022 को, अपीलार्थी ने पी. एफ. आई. से जुड़े कई अन्य अभियुक्तों के साथ इमारत अहमद पैलेस की पहली मंजिल पर एक बैठक-सह-प्रशिक्षण में भाग लिया। इस बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, पी. एफ. आई. सदस्यों के बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण, मुस्लिम सशक्तिकरण और पी. एफ. आई. के लिए भविष्य की योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उसने बताया कि संरक्षित गवाह जेड ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर एक नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर विचार करने के बाद, प्रशिक्षित पी. एफ. आई. सदस्यों को धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने में शामिल चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें मारने के निर्देश जारी किए गए थे। विद्वान ए. एस. जी. ने बताया कि आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.26 से पता चलता है कि 12 मई 2022 को रु. 25, 000/- एक फरार आरोपी के खाते से अपीलार्थी के पुत्र खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने प्रस्तुत किया कि किराया समझौता फर्जी था और पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाया गया था, और अपीलार्थी ने जानबूझकर पहली मंजिल के परिसर को पी. एफ. आई. की गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। वह प्रस्तुत करेंगी कि आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में पर्याप्त सामग्री थी, जो दर्शाती है कि यू. ए.

पी. ए. की धारा 13,18,18ए और 20 के तहत दंडनीय अपराधों में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। उसने बताया कि आरोपी नं। सं. 1, जिनके नाम पर पहली मंजिल की किरायेदारी दिखाई गई थी, वे एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन-स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सक्रिय सदस्य थे।

प्रस्तुतियों का समावेश

4. अपीलार्थी को 12 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। अहमद पैलेस की इमारत अपीलार्थी की पत्नी के नाम पर है। अपीलार्थी एक सेवानिवृत्त पुलिस सिपाही है। आरोप है कि 11 जुलाई 2022 की शाम को पुलिस ने अहमद पैलेस की पहली मंजिल पर छापा मारा। उस समय, पी. एफ. आई. से संबंधित आपत्तिजनक लेखों और दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई थी। आरोप-पत्र का अनुच्छेद 17.1 इस प्रकार है:

“17.1 बिहार पुलिस को फुलवारीशरीफ क्षेत्र में एकत्रित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की बिहार की प्रस्तावित यात्रा में बाधा डालने की योजना के बारे में जानकारी मिली थी। लगभग 1930 बजे, गुप्त सूचना पर, थाना फुलवारीशरीफ, पटना के पुलिस अधिकारियों द्वारा अतहर परवेज (ए-1) के किराए के घर/परिसर में छापा मारा गया और दस्तावेज के 05 सेट बरामद किए गए "भारत 2047 इस्लामी भारत के शासन की ओर, आंतरिक दस्तावेज:प्रचार के लिए नहीं, "पैम्फलेट" पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया 20 फरवरी, 2021 "-हिंदी में 25 प्रतियां और उर्दू में 30 प्रतियां, 49 कपड़े के झंडे, 02 पत्रिकाएं" मुल्क के लिए पॉप्युलर फ्रंट के साथ "और फरहत बानो द्वारा किराएदार अतहर परवेज (ए-1) अब्दुल कयूम अंसारी के पुत्र साथ गैर-

न्यायिक डाक टिकट पर किराए के समझौते की एक प्रति। तत्काल मामले में बरामद सामान और आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन (ए-2) के सिम कार्ड वाला एक सैमसंग मोबाइल फोन जब्त किया गया। वे भारत विरोधी गतिविधियों से संबंधित थे। .

5. प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए आरोप पत्र के अन्य पैराग्राफ निम्नलिखित हैं:

“17.16 संरक्षित गवाह- "जेड" ने आगे कहा कि 29 मई 2022 को, इस आपराधिक साजिश में अतहर परवेज (ए-1) और अन्य लोगों द्वारा किराए पर दिए गए आवास, अहमद पैलेस, फुलवारीशरीफ परना में एक बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक के रियाज फिरंगीपेट (ए-20) ने की और महबूब आलम नदवी (ए-7), सनाउल्लाह (ए-5), रियाज मौरीफ (ए-4), महबूब-उर-रहमान (ए-11), एहसान परवेज (ए-7), अंसारुल हक (ए-21), रियाज अहमद (ए-17), परवेज आलम (ए-26), तौसीफ आलम (ए-6), अतहर परवेज (ए-1), मो. पी. एफ. आई. से जुड़े जलालुद्दीन (ए-2) और अन्य लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, पी. एफ. आई. सदस्यों के बुनियादी और अग्रिम प्रशिक्षण, मुस्लिम सशक्तिकरण और पी. एफ. आई. की भविष्य की योजना से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। संरक्षित गवाह-जेड ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद, प्रशिक्षित पी. एफ. आई. कैडरों को इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने में शामिल चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें मारने का निर्देश दिया गया था।

“15.5 जाँच के दौरान, अहमद पैलेस में स्थापित सीसीटीवी की हार्ड डिस्क/डीवीआर को पुलिस स्टेशन फुलवारीशरीफ, पटना के जाँच अधिकारी

द्वारा जब्त कर लिया गया था। सी. सी. टी. वी. फुटेज की दर्पण छवियाँ सी. डी. ए. सी., तिरुवनंतपुरम, केरल से प्राप्त हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज ने 6 और 7 जुलाई, 2022 को अहमद पैलेस, फुलवारीशरीफ, पटना में अतहर परवेज (ए-1) सहित नामित अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज ने यह भी पुष्टि की कि पीएस फुलवारीशरीफ की पुलिस ने अतहर परवेज (ए-1) और मोहम्मद की उपस्थिति में शाम करीब 7 बजे अहमद पैलेस फुलवारीशरीफ की पहली मंजिल पर छापा मारा। जलालुद्दीन (ए-2)। इसने यह भी स्थापित किया कि मोहम्मद जलालुद्दीन (ए-2) ने पुलिस के छापे से पहले अहमद पैलेस, फुलवारीशरीफ, पटना की पहली मंजिल से वस्तुओं को स्थानांतरित करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।

“17.2 जांच में पता चला कि थाना फुलवारीशरीफ, पटना की पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मो. घर के मालिक जलालुद्दीन (ए-2) ने खुलासा किया कि उनके घर की पहली मंजिल को अतहर परवेज (ए-1) ने प्रशिक्षण देने के लिए किराए पर लिया था। 6 और 7 जुलाई 2022 को यहां प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी उपस्थित थे।

.....”

“17.26 जाँच के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा वाल्मी, पटना से एस. बी. आई. खाता संख्या 33767976372 का खाता विवरण माँगा गया और उसका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण पर यह पता चला कि 12.05.2022 पर, रु। 25, 000/- आमिर जलाल पुत्र- मोहम्मद खाते में स्थानांतरित किए गए। पंजाब नेशनल बैंक, भरवाड़ा, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर से जलालुद्दीन (ए-2) खाता सं। 0772010316309 ऑफ साकिब अहमद, पुत्र- मोहम्मद नयाज अहमद

अखुली भांडपुर कटड़ा, मुजफ्फरपुर, बिहार। उक्त साकिब अहमद के मोबाइल नंबर 9262711612 के कॉल डेटा रिकॉर्ड के विश्लेषण पर यह पाया गया कि यह भीड़ संबंधित तिथियों पर आरोपी सनाउल्लाह (ए-3) के साथ जुड़ी थी, जिससे पुष्टि हुई कि उक्त राशि सनाउल्लाह (ए-5) के निर्देश पर हस्तांतरित की गई थी। ”

6. इमारत की पहली मंजिल को किराए पर देने के संबंध में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि हालांकि भूमि और इमारत अपीलार्थी की पत्नी के नाम पर है, वह केवल एक नाम ऋणदाता है। अपीलार्थी ने 19 अप्रैल 2005 को रुपये 1,25,000/- के मूल्य पर संपत्ति खरीदी। काउंटर में, प्रतिवादी ने अपीलार्थी के प्रकटीकरण/इकबालिया बयान पर भरोसा किया है। इस तरह का बयान सबूत में स्वीकार्य है या नहीं, यह अलग बात है। प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए अपीलार्थी के बयान में कहा गया है कि अभियुक्त नं.1, अतहर परवेज, अप्रैल 2022 में अपने बड़े पुत्र-आमिर जलाल खान से मिले और पहली मंजिल किराए पर लेने पर चर्चा की। उसे बनाने के लिए। अपीलार्थी के बड़े पुत्र-आमिर जलाल खान ने कहा 25,000/- प्रति माह का किराया। उसके बाद, बातचीत हुई, और अंत में, किराया रुपये 16,000 प्रति माह तय किया गया। अभियुक्त सं. 1 आमिर जलाल खान को रुपये 5,000/- का अग्रिम दिया। इसके बाद, रु 25, 000/- अभियुक्त सं. 1 आमिर जलाल खान के खाते में और शेष राशि रु 2,000/- पट्टे के निष्पादन के समय का भुगतान किया गया था। अपीलार्थी के बयान में यह कहा गया है कि रु. 32,000/- का भुगतान दो महीने के लिए अग्रिम किराए के रूप में किया गया था। बयान में, अपीलार्थी ने कहा कि अभियुक्त सं.1 उन्हें पी. एफ. आई. संगठन के बारे में जानकारी दी। अपीलार्थी ने कहा कि बिहार और अन्य राज्यों के लोग आरोपी सं..उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें संदेह था कि पुलिस की छापेमारी होगी, इसलिए उन्होंने पहली मंजिल के परिसर में रखी वस्तुओं जैसे गैस सिलेंडर आदि को हटा दिया। यहां

तक कि आरोपी सं. 1 का बयान काउंटर में भरोसा करने से वही तथ्य मिलते हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के तथाकथित खोज बयान सहित अभिलेख की सामग्री से पता चलता है कि इमारत की पहली मंजिल पर स्थित परिसर अहमद पैलेस को आरोपी सं. 1, जो रुपये 16,000/- प्रति माह का किराया देने के लिए सहमत हुए और रु 32,000/- दो महीने के किराए के लिए। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता जानता था कि सह-अभियुक्त अतहर परवेज पी. एफ. आई. से जुड़ा था, इसे यू. ए. पी. ए. की धारा 2 (एम) के अर्थ के भीतर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा, आरोप पत्र में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी नंबर 1 को पहली मंजिल का परिसर किराए पर देने से पहले अपीलकर्ता का पीएफआई के साथ कोई संबंध था।

7. लगभग रु. 25, 000/- अपने खाते में अपीलार्थी पुत्र द्वारा प्राप्त, प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए अपीलार्थी के तथाकथित खोज बयान में एक स्पष्टीकरण है। इसलिए, जो रिकॉर्ड में लाया गया है वह यह है कि अपीलार्थी पुत्र ने अभियुक्त सं. 1 के साथ बातचीत की अभियुक्त सं.1, पहली मंजिल पर परिसर अभियुक्त सं.1 रुपये 16,000/- प्रति माह के मासिक किराए पर, और अपीलार्थी पुत्र द्वारा उसके खाते में प्राप्त राशि दो महीने के लिए किराए के अग्रिम के आंशिक भुगतान के लिए थी।
8. अब हम अपीलार्थी के खिलाफ अन्य परिस्थितियों पर आते हैं। आरोप पत्र के पैराग्राफ 15.5 में, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने 11 जुलाई 2022 को छापेमारी से पहले पहली मंजिल से कुछ वस्तुओं को स्थानांतरित कर दिया था। अपने काउंटर में प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए अपीलार्थी के खोज कथन में, अपीलार्थी ने कहा कि उसने पहली मंजिल के परिसर में गैस सिलेंडर आदि जैसी वस्तुओं को रखा था, जिन्हें उसने हटा दिया था।

9. 11 जुलाई 2022 को पहली मंजिल के परिसर में छापेमारी में, आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.1 में बताए गए कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं दिखाई गई है। आरोप पत्र में "भारत 2047 इस्लामी भारत के शासन की ओर" शैली वाले दस्तावेज की सामग्री का विस्तार से वर्णन किया गया है। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि उक्त दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि उक्त दस्तावेज भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के बारे में थे। यह ध्यान देने योग्य है कि आरोप पत्र में अपीलार्थी द्वारा पहली मंजिल के परिसर से कथित रूप से पहले स्थानांतरित की गई वस्तुओं की प्रकृति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यदि अपीलार्थी पी. एफ. आई. द्वारा प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है, तो वह आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.1 में उल्लिखित सामग्री को स्थानांतरित कर देता। सैयद अबू मोनवर के एक बयान से पता चलता है कि उक्त इमारत के भूतल पर दुकानें, पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं आदि जैसे वाणिज्यिक परिसर थे। यदि अपीलार्थी पहली मंजिल के परिसर को किराए पर देकर पी. एफ. आई. की आपत्तिजनक गतिविधियों के संचालन की अनुमति देना चाहता, तो उसने सी. सी. टी. वी. कैमरे नहीं लगाए होते।
10. अब, हम विद्वान ए. एस. जी. द्वारा निर्भर परिस्थितियों की ओर मुड़ते हैं, जो पैराग्राफ 17.16 में है। पैराग्राफ 17.16 का उद्देश्य संरक्षित गवाह जेड ने जो कहा है उसे पुनः प्रस्तुत करना है। हम उक्त अनुच्छेद को फिर से दोहराते हैं, जो इस प्रकार है:

“17.16 संरक्षित गवाह-“जेड” ने आगे कहा कि 29 मई 2022 को, इस आपराधिक साजिश में अतहर परवेज (ए-1) और अन्य लोगों द्वारा किराए पर दिए गए आवास, अहमद पैलेस, फुलवारीशरीफ परना में एक बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक के रियाज फिरंगीपेट (ए-20) और अनुमानित 40-45 व्यक्तियों के साथ महबूब

आलम नदवी (ए-7), सनाउल्लाह (ए-5), रियाज मौरीफ (ए-4), महबूब-उर-रहमान (ए-11), एहसान परवेज (ए-7), अंसारुल हक (ए-21), रियाज अहमद (ए-17), परवेज आलम (ए-26), तौसीफ आलम (ए-6), अतहर परवेज (ए-1), मोहम्मद. पी. एफ. आई. से जुड़े जलालुद्दीन (ए-2) और अन्य लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, पी. एफ. आई. सदस्यों के बुनियादी और अग्रिम प्रशिक्षण, मुस्लिम सशक्तिकरण और पी. एफ. आई. की भविष्य की योजना से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। संरक्षित गवाह-जेड ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद, प्रशिक्षित पी. एफ. आई. कैडरों को इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने में शामिल चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें मारने का निर्देश दिया गया था। .

इस प्रकार, पैराग्राफ 17.16 संरक्षित गवाह जेड के बयान को पुनः पेश करने का तात्पर्य है। हमारे पहले के आदेश के संदर्भ में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष दर्ज संरक्षित गवाह जेड के बयान का अनुवादित संस्करण एक सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया है। हम पाते हैं कि बयान आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.16 में बताए गए बयान से काफी अलग है।

11. बयान के अवलोकन से पता चलता है कि संरक्षित गवाह जेड ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि अपीलार्थी ने 29 मई 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया था। उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले कई लोगों के नाम तय किए हैं। अपीलार्थी का नाम निर्धारित नामों में शामिल नहीं है। वास्तव में, संरक्षित गवाह जेड का बयान इंगित करता है कि बैठक के बाद, अपीलार्थी को इमारत के मालिक के रूप में पेश किया गया था। पैराग्राफ 17.16 में आरोप लगाया गया है कि संरक्षित गवाह जेड ने कहा कि बैठक में संगठन के विस्तार, पी. एफ. आई. सदस्यों के बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण और भविष्य की

पी. एफ. आई. योजनाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई और प्रशिक्षित पी. एफ. आई. कैडर को एक नूपुर शर्मा को हटाने का निर्देश दिया गया। संरक्षित गवाह जेड के बयान में, वह सब नहीं पाया जाता है। वास्तव में, संरक्षित गवाह जेड ने कहा कि बैठक के दौरान, मुसलमानों की स्थिति को मजबूत करने, उन्हें बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने और मुसलमानों की शिक्षा, राजनीति और प्रशासन और मुस्लिम सशक्तिकरण की स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। गवाह के बयान के अनुसार, हम पाते हैं कि 29 मई 2022 को आयोजित बैठक में पी. एफ. आई. की गतिविधियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। गवाह के अनुसार, नूपुर शर्मा को मारने का निर्देश जून 2022 में जारी किया गया था, न कि 29 मई 2022 की बैठक में। हम संरक्षित गवाह जेड के कथन को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं संरक्षित गवाह जेड के रूप में इसे एक सीलबंद आवरण में रखा गया है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अनुच्छेद 17.16 में जो पुनः प्रस्तुत किया गया है वह सही नहीं है। गवाह जेड के वास्तविक बयान के भौतिक हिस्से को आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.16 में पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है। कई चीजें जो गवाह जेड को संरक्षित करती हैं, वे पैराग्राफ 17.16 में शामिल नहीं की गई हैं। दुर्भाग्य से, पैराग्राफ 17.16 कुछ बयानों को संरक्षित गवाह जेड के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जिसे उन्होंने नहीं बनाया। एन. आई. ए. को इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। जाँच तंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन, इस मामले में, अनुच्छेद 17.16 इसके विपरीत इंगित करता है।

12. अब, हम यू. ए. पी. ए. के तहत जमानत से संबंधित प्रावधान पर आते हैं, जो यू. ए. पी. ए. की धारा 43डी की उप-धारा 5 है, जो इस प्रकार है:

“43-डी. संहिता के कुछ प्रावधानों के संशोधित अनुप्रयोग -

.....

(5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है:

बशर्ते कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय, केस डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट के अवलोकन पर यह राय रखता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है।

.....”

13. विद्वान ए. एस. जी. ने मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय गुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य।² पर भरोसा किया राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली³, के मामले में अपने पहले के निर्णय पर व्यापक रूप से विचार किया गया जो धारा 43 डी (5) की व्याख्या से संबंधित है। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 32 इस प्रकार है:

“32. इस संबंध में हमें वटाली मामला [एन. आई. ए. बनाम जहूर अहमद शाह वटाली, (2019) 5 एस. सी. सी. 1:(2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 383] से आगे देखने की जरूरत नहीं है ने यू. ए. पी. अधिनियम के तहत जमानत सीमाओं के अपने आवेदन में अदालतों को जिस दृष्टिकोण में भाग लेना चाहिए, उस पर विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। पैराग्राफ 23 से

24 और 26 से 27 के अवलोकन पर, निम्नलिखित 8-सूत्री प्रस्ताव सामने आते हैं और उनका सारांश इस प्रकार है:

32.1. "प्रथम दृष्टया सत्य" का अर्थ:

इसके विपरीत, सामग्री में अपराध करने में अभियुक्त की संलिप्तता दिखानी चाहिए। कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यों या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए सामग्री/साक्ष्य अच्छे और पर्याप्त होने चाहिए, जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा खंडन या खंडन नहीं किया जाता है।

32.2. प्री-चार्ज-शीट, पोस्ट-चार्ज-शीट और पोस्ट-चार्ज पर संतुष्टि की डिग्री-तुलना:

“26. ... एक बार आरोप तय हो जाने के बाद, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि न्यायालय के समक्ष सामग्री पर एक बहुत मजबूत संदेह स्थापित किया गया था, जिसने न्यायालय को आरोप तय करने को सही ठहराने के लिए अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित किया। उस स्थिति में, अभियुक्त को न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए एक कठिन कार्य करना पड़ सकता है कि आरोप पत्र (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) के साथ प्रस्तुत सामग्री यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं बनाती है कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। वर्तमान मामले की तरह संहिता की धारा 173 के तहत की गई पहली रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा इसी तरह की राय बनाने की आवश्यकता है। ”

32.3. तर्क, आवश्यक लेकिन साक्ष्य का कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं

“24. ... इस चरण में न्यायालय द्वारा की जाने वाली कवायद - जमानत देने या न देने के लिए कारण बताना - साक्ष्य के गुण या दोष पर चर्चा करने से बिल्कुल अलग है। इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ”

32.4. व्यापक संभावनाओं पर एक निष्कर्ष दर्ज करें, जो संदेह से परे प्रमाण पर आधारित न हो:

“न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कथित अपराध करने या अन्यथा करने में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करे। ”

32.5. धारा 43-डी (5) के तहत सीमा की अवधि:

“26. ... विशेष प्रावधान, 1967 अधिनियम की धारा 43-डी, 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के चरण से लेकर उसके मुकदमे के समापन तक लागू होती है। ”

32.6. अभिलेख पर सामग्री का विश्लेषण "संपूर्ण" के रूप में किया जाना चाहिए; कोई टुकड़ों में विश्लेषण नहीं।

“27. ... जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई और रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई सामग्री की समग्रता और केस डायरी को शामिल करने की आवश्यकता है, न कि अलग-अलग साक्ष्यों या परिस्थितियों का विश्लेषण करके। ”

32.7. दस्तावेजों की सामग्री को सही माना जाना चाहिए:

“27. ... न्यायालय को दस्तावेज़ की सामग्री को देखना चाहिए और इस तरह के दस्तावेज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ”

32.8. अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है:

अभियुक्त के खिलाफ आरोप के समर्थन में जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है और इसे दूर नहीं किया जाता है या गलत साबित नहीं किया जाता है। किसी भी मामले में मामले में, साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के आधार पर, इस स्तर पर दस्तावेज़ को त्यागने का प्रश्न अनुमेय नहीं है। ”

(जोर दिया गया)

14. थवाहा फसल बनाम भारत संघ,⁴ के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय है, जो फिर से यू. ए. पी. ए. की धारा 43 डी (5) के दायरे से संबंधित है। जहूर अहमद शाह वटाली³, के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद, वास्तव में, पैराग्राफ 24 में, मामले को व्यापक रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद, पैराग्राफ 26 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“26. इसलिए, एक अभियुक्त द्वारा दायर जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय, जिसके खिलाफ 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है, अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप है प्रथम दृष्टया सच है। यदि अदालत अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, तो आरोपी जमानत का हकदार है। इस प्रकार, जांच का दायरा यह तय करना है

कि अध्याय IV और VI के तहत कथित अपराधों के आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है या नहीं। यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, उचित आधार होने चाहिए। हालांकि, अदालत से धारा 43-डी की उप-धारा (5) द्वारा आवश्यक प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे की जांच करते समय एक छोटा मुकदमा आयोजित करने की उम्मीद नहीं है। न्यायालय को साक्ष्य के गुण-दोष की जांच नहीं करनी चाहिए। यदि आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, तो अदालत को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आरोप-पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री की जांच करनी होगी कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। ऐसा करते समय, अदालत को आरोप-पत्र में सामग्री को वैसे ही लेना पड़ता है जैसे वह है। ”

(जोर दिया गया)

15. जैसा कि थवाहा फसल⁴ के मामले में कहा गया है, 4 न्यायालय को यह तय करने के लिए आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री की जांच करनी होगी कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। ऐसा करते समय, अदालत को आरोप पत्र को जैसा है वैसा ही लेना चाहिए।
16. अब हम अपीलार्थी के खिलाफ कथित अपराधों पर आते हैं। अपीलार्थी के खिलाफ यू. ए. पी. ए. की धारा 13, 18, 18 ए और 20 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। धारा 13 इस प्रकार है:

“13. गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा। .

(1) जो कोई भी-

(ए) भाग लेता है या करता है, या

(ख) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए अधिवक्ता, प्रोत्साहन, सलाह या उकसाना, सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई भी, किसी भी तरह से, धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित किसी भी संघ की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में सहायता करता है, उस अधिसूचना के बाद जिसके द्वारा इसे इस तरह घोषित किया गया है, उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गया है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा की कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच की गई किसी संधि, समझौते या समझौते पर या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई किसी बातचीत पर लागू नहीं होगी। ”

गैरकानूनी गतिविधि शब्द को धारा 2 (ओ) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“2 परिभाषाएँ। –

(ओ) किसी व्यक्ति या संघ के संबंध में "गैरकानूनी गतिविधि" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई कार्रवाई (चाहे वह कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा, या तो बोली या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा),-

(i) जिसका किसी भी आधार पर भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से का समर्पण या संघ से भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से का अलगाव करने का इरादा है या जो

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ऐसा समर्पण या अलगाव लाने के लिए उकसाता है; या (2024) 8 एस. सी. आर.

(ii) जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता है, सवाल करता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या

(iii) जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या पैदा करने का इरादा रखता है;

.....”

यू. ए. पी. ए. की धारा 18 और 18ए इस प्रकार है:

“18. षड्यंत्र आदि के लिए सजा – जो भी षड्यंत्र करना या करने का प्रयास करना, या वकालत करना, बढ़ावा देना, सलाह देना या उकसाना, प्रत्यक्ष रूप से या जानबूझकर किसी आतंकवादी कार्य या आतंकवादी कार्य की तैयारी के लिए किसी भी कार्य को करने में सुविधा प्रदान करता है, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

18ए. आतंकवादी शिविरों के आयोजन के लिए सजा। जो कोई भी आतंकवाद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी भी शिविर या शिविर का आयोजन करता है या आयोजित कराता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ”

आरोप पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी ने यू. ए. पी. ए. में परिभाषित गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लिया है या उसे अंजाम दिया है। यह

दिखाने के लिए कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत की, उसे उकसाया या उकसाया। धारा 15 (1) में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। यह मानते हुए कि सह-अभियुक्त आतंकवादी कृत्यों में लिप्त थे या आतंकवादी कृत्यों के लिए कोई तैयारी कर रहे थे, रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि किसी भी आतंकवादी कृत्य को करने की कोई साजिश थी जिसमें अपीलार्थी एक पक्ष था। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि अपीलार्थी ने आतंकवादी कृत्यों या किसी प्रारंभिक गतिविधि की वकालत की, उसे उकसाया, सलाह दी या उकसाया।

17. हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अपीलार्थी पुत्र ने पहली मंजिल को किराए पर देने के लिए बातचीत की थी। आरोप-पत्र को सही मानते हुए, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दर्ज करना संभव नहीं है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर आतंकवादी कृत्यों को करने या तैयार करने में सहायता की पहली मंजिल के परिसर को किराए पर देकर। पुनः, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र में कोई आरोप नहीं है कि उसने आतंकवाद में प्रशिक्षण देने के लिए कोई शिविर आयोजित किया था।

18. अब हम यू. ए. पी. ए. की धारा 20 पर आते हैं, जो इस प्रकार है:

“20. आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने पर सजा या संगठन— कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

धारा 2 (एल) में आतंकवादी गिरोह को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“2 परिभाषाएँ। —.....

(एल) "आतंकवादी गिरोह" का अर्थ है आतंकवादी संगठन के अलावा कोई भी संगठन, चाहे वह व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कृत्य से संबंधित हो या उसमें शामिल हो। ;

.....”

आरोप पत्र में यह भी आरोप नहीं है कि अपीलार्थी किसी आतंकवादी गिरोह का सदस्य था। जहाँ तक किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य होने के दूसरे भाग के संबंध में, धारा 2 (एम) के अनुसार, एक आतंकवादी संगठन का अर्थ है पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या उसी नाम के तहत काम करने वाला संगठन जिसे संगठन सूचीबद्ध किया गया था। आरोप पत्र में धारा 2 (एम) के अर्थ के भीतर आतंकवादी संगठन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका अपीलार्थी सदस्य था। हम पाते हैं कि पी. एफ. आई. एक आतंकवादी संगठन नहीं है, जैसा कि पहली अनुसूची से स्पष्ट है।

19. इसलिए, आरोप पत्र को सीधे पढ़ने पर, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ यू. ए. पी. ए. के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप प्रथम दृष्टया सच है। हमने आरोप पत्र और गवाह जेड का बयान ले लिया है क्योंकि वे एक लघु-परीक्षण किए बिना हैं। हमने पहले जो माना है, उसे देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दर्ज करना असंभव है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि यू. ए. पी. ए. के तहत अपराध करने के अपीलार्थी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच था। अपीलार्थी का कोई पूर्ववृत्त अभिलेख पर नहीं लाया गया है।
20. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत याचिका को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।

21. फैसला देने से पहले, हमें यहां यह उल्लेख करना चाहिए कि विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र की सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया। शायद पी. एफ. आई. की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, और इसलिए, अपीलार्थी के मामले की उचित रूप से सराहना नहीं की जा सकी। जब जमानत देने के लिए मामला बनाया जाता है, तो अदालतों को जमानत देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन, अदालतों का कर्तव्य कानून के अनुसार जमानत देने के लिए मामले पर विचार करना है। "जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है "एक तय कानून है। यहां तक कि वर्तमान मामले जैसे मामले में भी जहां संबंधित कानूनों में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें हैं, वही नियम केवल संशोधन के साथ लागू होता है कि जमानत तब दी जा सकती है जब कानून की शर्तें पूरी हो जाएं। नियम का मतलब यह भी है कि एक बार जमानत देने के लिए मामला बना लिया जाए, तो अदालत जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती है। यदि अदालतें योग्य मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देती हैं, तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा।
22. इसलिए, विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। अपील की अनुमति है। अपीलार्थी को विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। उस उद्देश्य के लिए, अपीलार्थी को आज से अधिकतम 7 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। विशेष न्यायालय अपीलार्थी को उचित नियमों और शर्तों पर मुकदमे के समापन तक जमानत पर बढ़ा देगा। विशेष न्यायालय नियम और शर्तें तय करने से पहले प्रतिवादी के वकील को सुनेगा।

23. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में दर्ज अस्थायी निष्कर्ष केवल जमानत के अनुरोध पर विचार करने के लिए हैं। कारण अपीलार्थी के मामले तक ही सीमित हैं। सह-अभियुक्त के मुकदमे और मामलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार किया गया।

¹द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: विधि ठाकर, हॉनी. सहायक संपादक

(द्वारा सत्यापित: श्री कानू अग्रवाल, अधिवक्ता)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

* लेखक

1 [2024] 4 एससीआर 270:(2024) 6 एससीसी 591

2 [2024] 2 एससीआर 134:(2024) 5 एससीसी 403

3 [2019] 5 एससीआर 1060:(2019) 5 एससीसी 1

4 [2021] 8 एससीआर 797:(2022) 14 एससीसी 766